Setting up of the National Institute of Sports in Western Zone

220. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any final decision has been taken by Government on the location of the National Institute of Sports (NIS) in Western Zone; and

(b) what facilities and locations are being offered by the Gujarat and Maharashtra Governments for setting up of this Institute?

AN[illegible]ND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) According to information received from the Netaji Subhas National Institute of Sports, the State Government of Maharashtra has offered about 60 acres of land free of cost at Chikalthana, Aurangabad and has also agreed to contribute a sum of Rs. 1.00 crore towards construction of the Centre; the State Government of Gujarat has offered their Sports Complex at Gandhinagar including several play-fields and play-grounds, swimming pool, tennis courts, etc., and a hostel with a capacity of about 300 persons, on a long lease basis, free of charge.

Magnetotherapy

221. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to develop Magnetotherapy on a scientific basis to help poor patients of the country to get treatment at nominal cost; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

दिल्ली के अस्पतालों में दिल का वाल्व बदलने की सुविधा

२२. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली तथा भारत के अन्य भागों में किन-किन अस्पताल[illegible] का वाल्व बदलने की सुविधा उपलब्ध है और इस प्रकार के बदलाव पर कितना खर्चा आता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बीमारी से पीड़ित सबसे अधिक रोगी बिहार से आते हैं और आपरेशन के लिए प्रत्येक रोगी को दो से तीन वर्ष का समय दिया जाता है और इस अवधि के दौरान, कुछ रोगी तो आपरेशन कराने से पहले ही मर जाते हैं ; और

(ग) [illegible] तो सरकार ने इस संबंध में क्या [illegible] की है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) दिल्ली: 1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

2. गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, दिल्ली ।

भारत :

1. दक्षिणी रेलवे अस्पताल पैराम्बुर, मद्रास ।
2. क्रिश्चियन मडिकल कालेज, एवं अस्पताल वेल्लोर
3. के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई ।
4. बम्बई अ[illegible]ताल, बम्बई ।
5. श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं टैक्नालाजी संस्थान त्रिवेन्द्रम

6. स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ ।
7. एस० एस० के० एम० अस्पताल कलकत्ता ।
8. एन० एम० वाडिया हृदय रोग संस्थान, पुणे ।
9. अपोलो अस्पताल, मद्रास ।
10. निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद ।
11. चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, त्रिवेन्द्रम ।

जहां हर संस्थान में लागत अलग-अलग हो सकती है वहां सरकारी संस्थानों में औसत खर्च इस प्रकार है :—

1. ओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का खर्च 20 000 रु० है ।
2. कोरोनरी बाइपास सर्जरी का खर्च 15,000 रुपये है ।
3. कोरोनरी एंजियो-ग्राफी का खर्च 1500 रुपये है ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की गई है ।

अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा हड़ताल का आह्वाहन

223. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 31 मार्च, 1986 से हड़ताल करने का आह्वाहन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापनों में रखी गई मांगों में ये बातें शामिल हैं—सभी राज्यों में इसे माह के अन्दर चुंगी कर की समाप्ति, डीजल के मूल्य में 30 प्रतिशत की कटौती, पूरे देश में एक समान डीजल मूल्य, सातवीं योजना के पूर्वार्द्ध में मौजूदा सभी राजमार्गों के सड़क धरातल में सुधार, ट्रक और बसों की बाडी पर उत्पादन शुल्क में कटौती, लागत के आधार पर युक्तिपरक वाहन मूल्य, टायरों के संबंध में सत्यपाल समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वयन, नियमों एवं विनियमों, सड़क परिवहन संबंधी कराधान नियमों में एकरूपता, राष्ट्रीय परमिटों पर संयुक्त शुल्क में कटौती, उत्तर प्रदेश में जो सड़क ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन से संबद्ध नहीं है उनसे बिना उपयोग लिए गए ट्रांजिट पासों पर शुल्क लेने की प्रथा समाप्त करना, ट्रांसपोर्ट नगरों में पट्टे के आधार पर भूमि देना, वाहन खरीदने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से आसान ऋण और बीमा पालिसी का व्यापक मशावेश । ये सभी मांगें केन्द्र के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, उन्हें इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए लिख दिया गया है ।

Measures to Check up Dropouts in Schools

224. SHRIMATI KRISHNA KAUL:
SHRI K. VASUDEVA PANICKER:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Prime Minister has recently urged upon schools in the country to study the causes of dropouts and devise measures to check the same; and

(b) if so, what follow up action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Yes, Sir. While addressing the National Primary Education Conference at Delhi on 31-3-86 the Prime Minister has stressed the need to retain students in schools and to give attention to the problem of drop-outs.

(b) The causes responsible for drop-outs being many, a whole range of